

न्यायालय— सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमराँव

स्वत्व वाद सं० – 127 / 2019

सी०आई०एस० – 527 / 2019

नथुनी गड़ेरी उर्फ नथूनी पालवादी ।

बनाम्

सदीम मियों वगै०.....प्रतिवादीगण ।

आदेश

31.01.2025

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादी की ओर से दिनांक 12.11.2024 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी०पी०सी० को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष जो एक ही खानदान के हैं मुकदमा की जानकारी रखते हुए मुकदमा के दौरान विवादित ऐराजी खाता नं० 26, प्लॉट नं० 2580, रकवा 05 डी० नूरानी जामा मस्जिद मुस्लिम टोला साकिन— सलसला निर्देशक मो० रिजवान अली के पक्ष में दान पत्र दिनांक 13.08. 2024 को एवं प्लॉट नं० 1981 की 02 डी० भूमि अपने ही खानदान में दिनांक 13.08. 2024 को एक कित्ता रजिस्ट्री केबाला के माध्यम से आपस में खरीद—बिक्री किये है तथा अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त के आलोंक में मुकदमा के अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय ।

प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक 03.01.2025 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को कथन है कि विवादित ऐराजी प्रथम पक्ष की पूर्वजों की खातियानी व दखली ऐराजी है। उसी आधार पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने खाता सं० 26, प्लॉट नं० 1981, रकवा 02 डी० तथा खाता नं० 26, प्लॉट नं० 2580 को केबाला किये है तथा वादी द्वारा यह संशोधन आवेदन वाद को बिलम्बित करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का संशोधन आवेदन दिनांक 12.11.2024 खर्चा के साथ खारिज किया जाय ।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में डीड नं० 5613 दिनांक 13.08.2024 की छाया प्रति दाखिल किया गया है जिसमें जिसमें मो० बशीर अहमद द्वारा इम्तियाज मियों, मो० कलीम तथा मो० एहसान

लगातार

31.01.2025 अली को विवादित ऐराजी केबाला तहरीर किया गया है। एक अन्य डीड सं० 5620 दिनांक 13.08.2024 की छाया प्रति दाखिल किया गया है जिसमें मो० बशीर अहमद वगै० द्वारा नूरानी जामा मस्जिद मुस्लिम टोला साकिन— सलसला निर्देशक मौ० रिजवान अली के पक्ष में दान पत्र दिनांक 13.08.2024 तहरीर किया है। चूंकि यह मुकदमा के दौरान तहरीर किया गया है। अतः यह अनुवर्ती घटना है। उक्त संशोधन प्रस्तुत वाद के पूर्णरूपेण निस्तारण के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित पक्षकार आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते हैं। अतः वादी की ओर दाखिल संशोधन आवेदन स्वीकृत करने योग्य है। परन्तु वादी द्वारा उक्त आवेदन बिलम्ब से दाखिल किया गया है अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 12.11.2024 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी०पी०सी० को न्यायहित में मो० 500/- पाँच सौ रुपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय कोर्ट फीस के संबंध में संशोधन पश्चात सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करें। प्रतिवादी अगर चाहें तो अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक 25.02.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमराँव (बक्सर)